जब उम्मीदें खत्म हो जाती है तब जीवन में सुकून मिलना शुरू होता है।

– अज्ञात

शराबबंदी की नीति

राज्य में शराबबंदी की नीति की क्या गत हुई है, इसका इससे बड़ा सबूत और क्या हो सकता है? हालांकि ऐसे सबूत हमें बार–बार अलग–अलग राज्यों में मिलते रहे हैं। देश का कोई भी ऐसा राज्य या क्षेत्र नहीं है जहां शराबबंदी को पूरी तरह सफल माना जा सके।

अनुप शाह।।

चुनाव आयोग का आंकड़ा है कि बिहार में मौजूदा विधानसभा चुनावों के दौरान ही करीब 25 करोड़ रुपये मूल्य की गैरकानूनी शराब जब्त की गई है। यह मात्रा 2019 के आम चुनाव और 2015 के विधानसभा चुनाव के दौरान जब्त की गई शराब से ज्यादा है। राज्य में शराबबंदी की नीति की क्या गत हुई है, इसका इससे बड़ा सबूत और क्या हो सकता है? हालांकि ऐसे सबूत हमें बार–बार अलग–अलग राज्यों में मिलते रहे हैं। देश का कोई भी ऐसा राज्य या क्षेत्र नहीं है जहां शराबबंदी को पूरी तरह सफल माना जा सके।

बिहार में भी यह आरोप आम रहा है और बातचीत के दौरान भी लोग बताते हैं कि अवैध शराब की खरीद–बिक्री हो ही रही है, बस पहले की तरह खुलकर नहीं होती। जो काम पहले वैध तौर पर, पारदर्शिता के साथ, टैक्स जमा करके होता था, वही अब अपराध की तरह ढके–छुपे ढंग से और पुलिस–प्रशासन की सांठगांठ से किया जा रहा है। इससे जहां एक तरफ सरकार को राजस्व का भारी नुकसान हो रहा है, खजाना खाली होने के कारण जरूरी सरकारी नियुक्तियां नहीं हो पा रही हैं, वहीं राज्य में भ्रष्टाचार और आपराधिक प्रवृत्तियों को बढ़ावा मिल रहा है।

जहां तक लोगों के स्वास्थ्य और उनकी आदतों के सुधरने का सवाल है तो चूंकि चोरी–छुपे शराब उपलब्ध हो ही रही है, इसलिए उस मोर्चे पर भी कोई खास फायदा नहीं है। उलटे ऐसी आशंका बढ़ जाती है कि सस्ती और अवैध दारू के चक्कर में लोग जहरीली शराब के शिकार न बन जाएं। विभिन्न राज्यों में समय–समय पर ऐसी मौतें अखबारों की सुर्खियां बनती रहती हैं। खुद बिहार सरकार के आंकड़े बताते हैं कि लॉकडाउन से पहले तक 2 लाख 60 हजार लोगों पर दारूबंदी के उल्लंघन का मामला दर्ज हुआ था। कोर्ट में लंबित होने के चलते ऐसे मामले और बढ़ गए हैं। आज भी हाईकोर्ट में 40 हजार जमानत याचिकाएं अटकी हुई हैं। ऐसे बहुत से लोग हैं जो जमानत राशि न जुटा पाने की वजह से जेल में पड़े हुए हैं। स्वाभाविक रूप से इसका खामियाजा उनके परिवार वालों को भुगतना पड़ रहा होगा। इन तमाम मुसीबतों के पीछे वजह सिर्फ एक है– बुराइयों को दूर करने का गलत तरीका। बेशक, शराब एक बुराई है, जिसका अतिरेक व्यक्ति का स्वास्थ्य, धन और परिवार तक नष्ट कर सकता है। लेकिन सवाल यह है कि इस बुराई को नियंत्रित कैसे किया जाए। अब तक के अनुभव बार–बार साबित करते रहे हैं कि नशाखोरी जैसी आदतें कड़े कानून बनाकर और सख्त सजाएं देकर नहीं दूर की जा सकतीं, अलबत्ता इस कोशिश में भ्रष्टाचार जैसी अन्य कई बुराइयां जरूर जोर पकड़ने लगती हैं। बिहार में भी यही होता दिख रहा है। वक्त आ गया है कि बार–बार नाकाम साबित हुई शराबबंदी की नीति को लागू करते हुए उसका नुकसान उठाते रहने के बजाय इस नीति को पलटने का फैसला किया जाए। उम्मीद करें कि चुनाव नतीजों के बाद बिहार में बनने वाली नई सरकार अब तक के अनुभवों की रोशनी में उचित फैसला करने में देर नहीं लगाएगी।

तीन गलतियां

धर्म-दर्शन

अशोक वोहरा।

दुर्योधन ने बताई तीन गलतियां। श्रीकृष्ण ने सहजता से दुर्योधन से उसकी उन तीन गलतियों के बारे में पूछा तो उसने बताया, पहली गलती यह थी कि उसने स्वयं नारायण के स्थान पर उनकी नारायणी सेना को चुना। यदि नारायण युद्ध में कौरवों के पक्ष में होते, तो आज परिणाम कुछ और ही होता। दूसरी गलती उसने यह बताई की कि अपनी माता के लाख कहने पर भी वह उनके सामने पेड़ के पत्तों से बना लंगोट पहनकर गया। यदि वह नग्नावस्था में जाता, तो आज उसे कोई भी योद्धा परास्त नहीं कर सकता था। तीसरी और अंतीम गलती उसने की थी वो थी युद्ध में आखिर में जाने की भूल। यदि वह पहले ही जाता तो कई बातों को समझ सकता था और शायद उसके भाई और मित्रों की जान बच जाती।

संपादकीय

असर दूसरे राज्यों तक

युवाओं का समर्थन जुटाने के लिए दूसरे दलों को भी अपने राज्यों में सरकारी नौकरी का वादा करना ही होगा। युवाओं के सामने एक नजीर बन चुकी होगी कि बिहार में अगर वहां की सरकार ऐसा कर सकती है तो फिर हमारे राज्य में ऐसा क्यों नहीं हो सकता है? बिहार में ही तेजस्वी की घोषणा के बाद एनडीए और खासतौर पर बीजेपी किस तरह से दबाव में आई, उसका उदाहरण देखा ही गया है। तेजस्वी ने जब दस लाख सरकारी नौकरियों का वादा किया, तो पहले बीजेपी और जेडीयू ने उसका संज्ञान लेना भी जरूरी नहीं समझा। फिर उसका असर होते देखा तो यह कहकर उसे खारिज करने की कोशिश की कि इस घोषणा पर अमल हो ही नहीं सकता, क्योंकि इसके लिए राज्य को करीब 1.11 लाख करोड़ रुपयों की अतिरिक्त जरूरत होगी, और इतनी बड़ी रकम जुटा पाना मुमकिन नहीं। तेजस्वी ने इसका जवाब दिया कि खर्च में कटौती करेंगे और जरूरत महसूस होने पर मंत्रियों–विधायकों का वेतन कम कर देंगे। उसी वक्त राज्य में बीजेपी को यह अहसास हो गया था कि हाथ से बाजी निकले, उससे पहले कुछ करना चाहिए। बीजेपी ने भी अपने संकल्पपत्र में 19 लाख युवाओं को रोजगार देने की बात कही। बिहार के नतीजे आने के अगले छह महीने के अंदर चार प्रमुख राज्यों– वेस्ट बंगाल, तमिलनाडु, केरल और असम में राज्य विधानसभाओं के चुनाव होने हैं। सबसे पहले इन्हीं राज्यों में राजनीतिक दलों के सामने युवाओं के लिए सरकारी नौकरियां देने का वादा करने का दबाव देखा जाएगा।

इस योजना के असर का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि 2012 के चुनाव अभियान के दौरान ही रोजगार केंद्रों पर अपना नाम दर्ज कराने के लिए युवाओं की लंबी–लंबी कतारें लगने लगी थीं।

अर्जेंडे का बदल जाना

नदीम।।

एक वक्त था जब बेरोजगारी भत्ता मुद्दा बना करता था। यूपी में मुलायम सिंह यादव ने इसकी शुरुआत की थी। उनकी पार्टी के घोषणापत्र में कहा गया था कि सत्ता में आने पर वह बेरोजगार युवाओं को बेरोजगारी भत्ता देगी। यह राशि दो हजार रुपये महीने की हुआ करती थी। यह घोषणा युवाओं के बीच खासे आकर्षण का केंद्र बनी थी और उस साल के चुनाव में समाजवादी पार्टी को मिली बढ़त में बेरोजगारी भत्ते का बहुत बड़ा योगदान माना गया था। इस योजना के असर का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि 2012 के चुनाव अभियान के दौरान ही रोजगार केंद्रों पर अपना नाम दर्ज कराने के लिए युवाओं की लंबी–लंबी कतारें लगने लगी थीं।

तमाम दूसरी पार्टियों ने पहले 'बेरोजगारी भत्ता' के कॉन्सेप्ट का विरोध किया था। तर्क यह था कि समाजवादी पार्टी का यह कदम युवाओं को निठल्ला बनाएगा, क्योंकि बैठे–बिठाए जब युवाओं को सरकारी खजाने से दो हजार रुपये महीने मिलने लगेंगे, तो फिर रोजगार तलाशने की उनकी इच्छा स्वाभाविक ही कम हो जाएगी। लेकिन बाद में देखा यह गया कि जिन पार्टियों ने इसका विरोध किया था, उन्होंने खुद

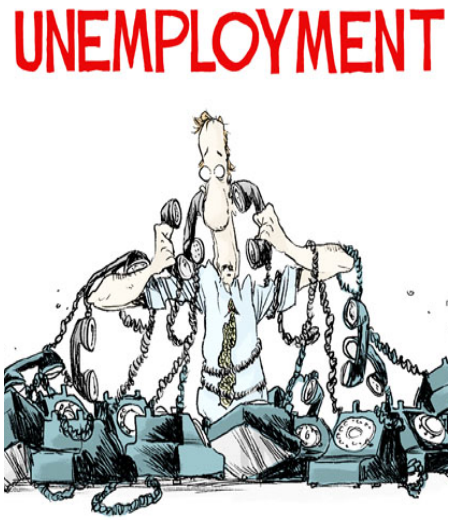

अलग–अलग राज्यों में इसी फॉर्म्युले को अपनाया। पार्टियों को लगने लगा था कि यह एक जिताऊ फॉर्म्युला है, साथ ही इसमें अपनी कोई जिम्मेदारी नहीं। अगर नौकरियों की बात की होती, तो नौकरी पैदा करनी पड़ती, लेकिन बेरोजगारी भत्ते के लिए तो अपनी तरफ से कोई कोशिश ही नहीं करनी थी। सत्ता में आने पर सरकारी खजाने से रोजगार केंद्रों में दर्ज युवाओं को बेरोजगारी भत्ता बांट देना है। यह बात दीगर है कि बाद के दिनों में युवाओं के बीच बेरोजगारी भत्ते ने भी आकर्षण खो दिया और उसकी जगह फ्री लैपटॉप, स्मार्ट फोन और वाई–फाई जैसी घोषणाओं ने ले लिया।

यह संदर्भ इसलिए कि बिहार विधानसभा चुनाव के नतीजे आज (10 नवंबर को) आ रहे हैं। अगर ये नतीजे एग्जिट पोल के नतीजों के अनुरूप हुए, तो बिहार में तेजस्वी यादव के नेतृत्व में महागठबंधन की सरकार बननी तय है। तेजस्वी यादव की इस कामयाबी के पीछे जिस फैक्टर को सबसे अहम माना जा रहा है, वह है दस लाख सरकारी नौकरियों का वादा। ऐसा कहा जा रहा है कि तेजस्वी के इस वादे ने जादू जैसा काम किया है। निराश युवाओं में नई उम्मीद जगाई और तमाम पूर्वाग्रहों को लांघते हुए उन्होंने तेजस्वी के साथ अपने को खड़ा किया। ऐसा नहीं कि बेरोजगारी पहले कभी नहीं रही, लेकिन पिछले कुछ सालों में रोजगार के अवसर सीमित होते गए और कई अलग–अलग सर्वे में यह बात सामने आई कि भारत में इस वक्त बेरोजगारी की दर शिखर पर है।

रही सही कसर कोरोना ने पूरी कर दी। बड़ी तादाद में लोगों की नौकरियां छूट गईं और मंदी का जो माहौल बना, उसमें फिलहाल रोजगार के नए अवसर आने की संभावनाएं भी न्यूनतम हो गईं। ऐसे में सरकारी नौकरियों का वादा ख्वाब के हकीकत में बदलने जैसा हो गया।

सूडोकु नवताल-5533

मध्यम

	8	1				2	5	
2								9
5			1		7	4		
9	5			4			2	
		3	9		6	7		
	7			8			1	5
		7	2		5			1
6								7
	1	5				6	9	

Jagrutidaur.com, Bangalore

- प्रत्येक पंक्ति में 1 से 9 तक के अंक भरे जाने आवश्यक हैं.
- प्रत्येक आड़ी और खड़ी पंक्ति में एवं 3×3 के वर्ग में किसी भी अंक की पुनरावृत्ति न हो इसका विशेष ध्यान रखें.
- पहले से मौजूद अंकों को आप हटा नहीं सकते.
- पहेली का केवल एक ही हल है.

सूडोकु नवताल -5532 का हल

5	9	4	2	3	6	1	8	7
8	7	3	1	4	5	2	9	6
6	1	2	8	7	9	3	5	4
1	6	7	9	8	2	4	3	5
3	8	5	4	1	7	6	2	9
2	4	9	6	5	3	7	1	8
7	5	6	3	9	1	8	4	2
4	2	1	5	6	8	9	7	3
9	3	8	7	2	4	5	6	1

अपना ब्लॉग

सरकारी नौकरी हमेशा सुरक्षित जोन में रखती

मोहन। एक सामान्य सी धारणा है कि सरकारी नौकरी व्यक्ति को हमेशा सुरक्षित जोन में रखती है, किसी भी तरह की स्थितियां आ जाएं कम से कम नौकरी नहीं जाती। चुनाव अभियान के दौरान जब युवाओं से यह पूछा जा रहा था कि तेजस्वी के सरकारी नौकरियों के वादे पर वे क्यों भरोसा कर रहे हैं, तो उनमें से कई का जवाब यह होता था कि अगर वह वादा नहीं पूरा करेंगे तो हम अब भी बेरोजगार हैं, तब भी बेरोजगार ही रहेंगे। हमारे पास खोने का जोखिम कुछ भी नहीं है, लेकिन अगर उन्होंने अपना वादा पूरा कर दिया तो एक अवसर तो होगा ही सरकारी नौकरी पाने का। इसी उम्मीद पर बिहार के युवाओं ने बेरोजगारी भत्ता पाने की कोई इच्छा भी नहीं जाहिर की। सरकारी नौकरी तो युवाओं की हमेशा से ही पहली पसंद रही है।